राज्य स्तरीय बैकर्स समिति, झारखण्ड

संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया

दिनांक : 11.08.2021

स्थान– बिरसामुंडा सभागार, एसएलबीसी कार्यालय, रांची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 76 वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 76वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन दिनांक 11.08.2021 को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति कार्यालय, रांची के बिरसामुंडा सभागार से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबन्धक श्री संजीव सिन्हा ने बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार श्री अबूबक्कर सिद्दीकी,भा०प्र०से०, सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार श्री अजय कुमार सिंह, भा०प्र०से०, विशेष सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार श्रीमती दीप्ती जयराज, नाबार्ड,झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबन्धक श्री जी. के. नायर, एसएलबीसी, झारखंड के महाप्रबंधक श्री उद्दालक भट्टाचार्य, निदेशक, कृषि विभाग, झारखंड सरकार श्रीमति निशा उरांव, एसएलबीसी, झारखंड के उप-महाप्रबंधक श्री गणेश टोप्पो , जेएसएलपीएस की सीईओ श्रीमति नैन्सी सहाय, भा०प्र०से० विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उंपस्थित थे।

इसके अतिरिक्त पीएफ़आरडीए के सहायक महाप्रबंधक श्री आशीष डोंगरे, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री पीयूष भट्ट एवं अन्य सभी बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुख प्रतिनिधि तथा सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं राज्य सरकार के अन्य विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े हुए थे। **संलग्नक–I में बैठक के सहभागियों की सूची संलग्न है।**

स्वागत भाषण- श्री उद्दालक भट्टाचार्य, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, एस एल बी सी,झारखंड का सम्बोधन

प्रारंभ में, श्री उद्दालक भट्टाचार्य, महाप्रबंधक, एस एल बी सी ने अतिथियों एवं सहभागियों का बैठक मे स्वागत किया। उन्होने एस एल बी सी बैठक की महत्ता एवं अपेक्षाओं पर गंभीरतापूर्वक चर्चा हेतु सभी सदस्यों को आग्रह किया। उन्होने बताया कि जून, 2021 तिमाही में कोविड महामारी के दूसरे लहर के कारण काफी चुनौतीपूर्ण रहा। झारखंड सहित पूरे देश ने इस महामारी में बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। महामारी से हमने बहुत कुछ सिखाया है, हालाँकि महामारी का असर कम होने के साथ ही अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही है। आशा है कि आने वाले कुछ महीनों में बैंकिंग क्षेत्र मे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे ।

उन्होने कहा कि 76वीं SLBC के Agenda Book से प्रतीत होता है कि जून,21 तिमाही में बैंकों द्वारा विभिन्न आयामों विशेषकर सामाजिक सुरक्षा योजना, डिजिटल बैंकिंग एवं Financial Inclusion मे अच्छी प्रगति हुई है। हालाँकि वर्तमान स्थिति के मद्देनजर बैंको को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार विभिन्न पहलुओ मे निश्चित दिशा में कार्य करने करने की आवश्यकता बतायी।

<u>श्री गणेश टोप्पो – उप महाप्रबंधक,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति,झारखंड का संबोधन</u>

उपमहाप्रबंधक श्री गणेश टोप्पो ने सभा को संबोधित करते हुये सदन को विगत तिमाही में एसएलबीसी एवं बैंको द्वारा हासिल की गयी उपलब्धियों से अवगत कराया।

- PFRDA द्वारा गत वर्ष SLBC झारखंड, राज्य के कुछ बैंको एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक को Certificate of Excellence तथा Award of Par excellence performance प्राप्ति की बधाई दी।
- सभा को बताया कि SLBC Jharkhand द्वारा जून तिमाही में सभी बैंको से data की रिपोर्टिंग Standardized automated data flow के आधार पर की गयी है, जिससे रिपोर्टिंग में काफी पारदर्शिता आई है।
- पिछली तिमाही की अपेक्षा विभिन्न पहलुओ (CD Ratio, Priority Sector Advance) मे गिरावट आने पर चिंता जाहिर की।
- राज्य सरकार के सहयोग से दिनांक 12 जुलाई 2021 से किसान क्रेडिट कार्ड ड्राइव के तहत 6.96 लाख आवेदन सृजित किए गए, जिनमे 1.57 लाख से अधिक आवेदन बैंको द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। राज्य सरकार के दिशानिर्देश द्वारा जिला स्तर पर विश्व आदिवासी दिवस (09.08.2021) के उपलक्ष्य पर KCC वितरण Camp का आयोजन कर प्रचुर मात्रा में ऋण वितरण किया गया है।
- उन्होने सभा को जानकारी दी कि राज्य सरकार द्वारा VLW एवं कृषक मित्र की सेवाएँ बैंक शाखाओं को प्राप्त हो रही हैं, जिससे कृषि ऋण वितरण में पहले की अपेक्षा प्रगति हो रही है। साथ ही साथ प्रखण्ड स्तर पर special BLBC करते हुए local level के stakeholders के बीच KCC ऋण वितरण की समीक्षा की जा रही है।
- बैंक शाखाओं को KCC ऋण वितरण के मार्गदर्शन हेतु NABARD द्वारा जारी FAQ का संदर्भ लेकर सभी आवेदनों को ससमय निष्पादित करना चाहिए।
- Secretary, Agriculture, GoJ के दिशा निर्देशानुसार वैसे केसीसी आवेदन जो कि बैंको द्वारा कुछ कमियो के कारण वापिस किए गए हैं उन्हे निदेशक, डेयरी एवं फिशेरी कार्यालय द्वारा खामियों को दूर करते हुए पुनः बैंक मे जमा करने को कहा है।
- श्री टोप्पो ने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंको को 80,000 आवेदन का लक्ष्य मार्च 2022 तक दिया गया है जिसके सापेक्ष 44,820 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमे 55% से अधिक आवेदनों की स्वीकृति की जा चुकी हैं साथ ही साथ **"स्वनिधि से समृद्धि:"** campaign के तहत गत सप्ताह रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में
  कैंप का आयोजन कर PM SVANidhi के ऋणी एवं उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी Coverage किया जा चुका है।
- उन्होने e -Stamping के संबंध में जानकारी दी कि राज्य–सरकार तथा वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के सहयोग से झारखंड राज्य में e-Stamping को लागू किया जा चुका है। हालांकि SLBC को अभी तक केवल तीन बैंको द्वारा ही उपयोग की जानकारी प्रदान की गयी है।
- राज्य मे जिन बैंकों द्वारा पिछले वर्ष ACP का लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ था वैसे 18 बैंको द्वारा अपने बैंक का SWOT Analysis का प्रस्तुतीकरन वर्तमान महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक श्री संजीव सिन्हा तथा रा॰स्त॰बै॰स॰ के समक्ष

किया गया जिसमे अपने बैंक की प्रगति बढ़ाने हेतु सुझाव प्राप्त हुए तदनुसार महाप्रबंधक द्वारा लक्ष्य भी बैंकों को प्रदान किये गए। उक्त बैंकों को अपनी प्रगति पुनः महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक तथा रा॰स्त॰बै॰स॰ के समक्ष प्रस्तुत करना है।

- गत एसएलबीसी की बैठक में Joint Secretary,वित्तीय सेवाए विभाग, श्री मदनेश कुमार मिश्रा जी के निर्देशानुसार सभी Private एवं Small finance बैंकों के साथ एसएलबीसी द्वारा अलग से बैठक आयोजित की गयी जिसमे Priority Sector lending एवं Govt sponsored Schemes में उनकी सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रत्येक बैंक से चर्चा करते हुए रणनीति बनाई गयी।
- आरबीआई के निर्देशानुसार राज्य में Cyber Incident reporting mechanism, Karnataka Model के आधार पर लागू करने के लिए राज्य के Major Banks एवं राज्य पुलिस विभाग के साथ विस्तृत चर्चा की गयी एवं झारखंड राज्य के लिए एक मॉडल तैयार किया गया जो कि राज्य मे लागू किया जा सके।
- तीन बैंक (Punjab National Bank, Canara Bank, Union Bank of India) की विशेष समिति द्वारा online Charge Creation के मुद्दे पर बनाए गए ड्राफ्ट पर राज्य के Major Banks के साथ चर्चा की गयी साथ ही साथ राज्य के revenue department के साथ चर्चा कर फ़ाइनल ड्राफ्ट बनाया गया।
- राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में राज्य के केसीसी ऋण के केवल Standard खातों को ही सम्मिलित किया गया, जिससे राज्य में ऋण वसूली का एक माहौल बना जिससे ऋण खातो।
- राज्य सरकार ने अब तक दस जिलों में सर्टिफिकेट ऑफिसर कि नियुक्ति की जा चुकी है,हालाँकि अन्य जिलो मे अविलंब नियुक्ति हेतु प्रयास करने की आवश्यकता बतायी।
- उन्होने कहा कि अब तक East Singhbhum जिले में 99.37% digitally coverage किया जा चुका है इस कार्य से प्रोत्साहित होते हुए RBI के दिशानिर्देशानुसार Ranchi जिले को भी Digitally आच्छादित करने हेतु अभियान शुरू किया गया है। आरबीआई के सहयोग से राज्य के सभी जिलों में बैंक ऑफ इंडिया एवं इंडियन बैंक द्वारा दिसम्बर 2021 तक 44 center for financial literacy की स्थापना की जानी है। जिनमे से दिनांक 31.07.2021 की रिपोर्ट के अनुदार कुल 30 CFLs की स्थापना की जा चुकी है, सीएफ़एल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन करते हुये वित्तीय शिक्षा दी जा रही है।
- उन्होने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या का 12.08% Scheduled Caste (SC) and 26.21% Scheduled Tribe (ST) हैं जबकि राज्य के कुल ऋण प्रवाह का केवल 9.09% ही एसटी/एससी वर्ग को दिया गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। राज्य में बढ़ता हुआ NPA भी हमारे लिए एक चैलेंज है, एनपीए का data देखने से पता चलता है कि कुछ बैंको का कुछ स्कीम मे खास तौर पर PMEGP में 100% है, जो कि बेहद सोचनीय विषय है, जिसकी तरफ सभी को ध्यान देने के आवश्यकता है।
- उन्होने विश्वास दिलाया कि आज की बैठक SLBC को एक नया आयाम देगी और आने वाले दिनों में अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए विशिष्ट दिशा प्रदान करेगी।

श्री जी. के. नायर – मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड,झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय का संबोधन

श्री नायर ने कोविड-19 महामारी के 2nd Wave के कारण कृषि क्षेत्र पर पड़ रहे दुष्प्रभाव की चर्चा करते हुये बताया कि कृषि क्षेत्र से जुड़े किसानों की मदद के लिए बैंकों को आगे आने की आवश्यकता है।

- राज्य में खरीफ के मौसम मे राज्य मे किसानों को पूंजी की आवश्यकता के मद्देनजर बैंकों से आग्रह किया कि कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु तत्परता दिखाने का आग्रह किया।
- उन्होने कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में रोजगार की कमी होने बात कही, हालांकि रिर्वस माइग्रेशन के कारण बाहर से आए मजदूर दूसरे स्टेट में वापस भी लौट रहे हैं। इस विषय पर पलायन रोकने हेतु अपने राज्य मे रोजगार शुरू करने हेतु ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता बतायी। उन्होने भारत सरकार की Agri Infra fund के अंतर्गत Horticulture के क्षेत्र में ऋण प्रवाह हेतु बैंकों को प्रोत्साहन देने की बात कही।

श्री संजीव सिन्हा, महाप्रबंधक, आरबीआई , राँची क्षेत्रीय कार्यालय का संबोधन

- श्री सिन्हा ने सभी उच्च पदाधिकारियों एवं सहभागियों का एसएलबीसी बैठक मे अभिवादन किया एवं जून ,21 तिमाही के डाटा का विश्लेषण करते हुए सभा को निम्न महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत कराया।
- सर्वप्रथम, ऋण जमा अनुपात के निरंतर गिरते हुए आँकड़ो पर चिंता जाहिर करते हुए सभा को जानकारी दी कि जून, 2021 तिमाही में राज्य का CD Ratio 37.04% तक आ चुका है, जो कि पिछली मार्च, 2021 तिमाही के CD Ratio 42.43% से काफी नीचे है। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के जून,2020 तिमाही में राज्य का CD Ratio 54.94% था।
- राज्य में बैंकों का NPA पिछली वित्तीय वर्ष 2020-21 के जून तिमाही से 5.22% बढ़कर जून, 2021 तिमाही में 9.82% हो गया है, यह काफी विचारणीय है। NPA के आँकड़ो में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि के कारण राज्य में बैंकों द्वारा दिये गए Government Sponserd Scheme के ऋण में भी दर्ज की गई है।
- उन्होने सभा को जानकारी दी कि राज्य के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रवाह में 30% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। उन्होने राज्य में ज्यादा शाखाओ वाले बैंकों का प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में कम share होने पर चिंता व्यक्त की।
- इस तिमाही मे बैंकों द्वारा Rationalisation of Branches के कारण राज्य में 43 ग्रामीण शाखाएँ कम होने पर चिंता जाहीर करते हुए बताया कि बैंको को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बैंकिंग सेवाए सुनिश्चित करनी चाहिए।
- उन्होने साइबर फ्रॉड को राज्य के सभी स्टेक होल्डेर्स के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या बताई। उन्होने साइबर फ्रॉड के रोकथाम हेतु Electronic Architecture सृजित करने का सुझाव दिया, जहाँ पुलिस एवं बैंक officials ऑनलाइन जानकारी साझा कर सकेंगें एवं संबन्धित विभाग द्वारा समय पर पूर्व-नियोजित कार्यवाही करते हुये खाताधारकों के जोखिम को कम किया जा सकेगा।
- उन्होने **Land Charge Creation By Bank** के संबंध में कहा कि बैंको की समिति द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से इस विषय पर कार्य किया जा रहा है, निश्चित तौर पर बैंकों को वास्तविक भूस्वामी को ऋण वितरण करने में सुविधा होगी। Digitilisation and Updation of Land Record के कारण राज्य के कृषि ऋण प्रवाह में भी काफी तेजी आएगी।

- 26 मार्च, 2021 को सम्पन्न विशेष एसएलबीसी की बैठक की कृत कार्यवाही के संबंध में कहा कि एसएलबीसी द्वारा सभी संबन्धित विभागों को पत्र लिखा गया है। उन्होने कहा कि केवल पत्र लिखने से कार्यवाही पूरी नहीं हो सकती है, जबतक इसमें कोई उपलब्धि न हो। अत: उन्होने सलाह दी कि एसएलबीसी की आगामी बैठकों में इस विषय की वास्तविक प्रगति की कृत कार्यवाही प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- उन्होने सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में Low Sanction, High rejections and Huge Pendency के संबंध में सलाह दी कि एसएलबीसी की प्रस्तावित बैठक के पहले बैंक एवं प्रायोजित एजेंसी को एक साथ बैठक कर आवेदनों के rejection के कारणों पर परिचर्चा के साथ ही साथ सुधार करने के उपायों पर भी चर्चा करनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की खामियाँ आवेदनों में ना हो तथा बैंक द्वारा ऋण प्रवाह में भी तेजी आएगी।
- उन्होने आगे कहा कि Small Financae Bank के डाटा को देख कर यह परिलक्षित होता है कि राज्य में Small Finance Banks के विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। उन्होने जानकारी दी कि आरबीआई द्वारा Collateral Free SHG Finance एवं Loan under Credit Guarantee Fund for Micro Units के लिए नवीनतम दिशा-निर्देश जारी किये है।
- अंत में उन्होने सदन को जानकारी देते हुये बताया कि आरबीआई द्वारा बैंकों पर System of Monetary Penalty के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है, अतः बैंको को एटीएम मे Cash की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।

<u>श्री आशीष डोंगरे,उपमहाप्रबंधक, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण का सम्बोधन:-</u>

- श्री आशीष डोंगरे ने एसएलबीसी झारखंड एवं सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में APY के अंतर्गत पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई दिया। उन्होने इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में जुलाई तक APY एनरोल्लमेंट मे 35% उपलब्धि होने की जानकारी दी।
- श्री डोंगरे ने पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बरौदा एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को APY enrollment में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बतायी।
- बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक एवं झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को इस वित्तीय वर्ष में जुलाई तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु बधाई दिया। साथ-ही-साथ उन्होने झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को पिछली वित्तीय वर्ष में पूरे देश के ग्रामीण बैंक (RRB Category) के वर्ग में 2nd स्थान प्राप्त करने की जानकारी दी।
- उन्होने सभा को जानकारी दिया कि सभी राज्यों के एनआरएलएम से जुड़े SHG Group के सदस्यों को APY enrollment के लिए झारखंड सहित सभी राज्य के एनआरएलएम को पत्र लिखा है, जिससे राज्य में APY enrollment में तेजी आने की संभावना है।
- PFRDA द्वारा चलाये जा रहे APY Citizen Choice Campaign की जानकारी देते हुए एसएलबीसी एवं सभी बैंकों से अनुरोध किया कि इस अवधि में अधिक से अधिक APY Enrollment करने हेतु प्रयास करें।
- अंत मे उन्होने राज्य के एनआरएलएम टीम तथा एसएलबीसी के साथ पीएफ़आरडीए की एक संयुक्त बैठक कराने हेतु अनुरोध किया।

<u>श्री अबूबक्कर सिद्दीकी, सचिव, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड सरकार का सम्बोधन</u>

- श्री अबूबक्कर सिद्दीकी ने सभा को जानकारी दी कि दिनांक 09.08.2021 को विश्व आदिवासी दिवस के दिन पूरे राज्य में बैंकों द्वारा 1.50 लाख केसीसी ऋण वितरित किए गए जिस पर माननीय मुख्यमंत्री ने भी प्रसन्नता जाहीर की।
- उन्होने सभा को जानकारी देते हुए बताया कि केसीसी अभियान के अंतर्गत अभी तक लगभग सात लाख केसीसी आवेदन सृजित किए जा चुके हैं जिसमे पीएम किसान लाभुकों के साथ राज्य के सभी किसानों को केसीसी जारी किया जाना है।
- सभा को जानकारी दी गयी कि राज्य में 30 लाख पीएम किसान के लाभुक हैं तथा राज्य में लगभग 50 लाख से ज्यादा किसान हैं। राज्य में जून, 2021 तक बैंकों की रिपोर्टिंग के अनुसार 13 लाख केसीसी जारी किये गए है। साथ ही राज्य सरकार ने 10 लाख केसीसी आवेदन सृजित करने का तत्काल लक्ष्य रखा है जिससे राज्य के सभी किसानो को केसीसी कार्ड जारी किया जाने हेतु मार्ग प्रशस्त हो।
- उन्होने आरबीआई महाप्रबंधक के वक्तव्य पर सहमति जताते हुये कहा कि केसीसी आवेदनों के निष्पादन में बैंकों द्वारा Reject किए गए आवेदनों की संख्या अधिक है। उन्होने बताया कि प्रत्येक केसीसी आवेदन को सृजित करने में जिला कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन से जुड़े कई अधिकारियों द्वारा काफी परिश्रम किया जाता है। अत: उन्होने बैंकों को सलाह दिया कि वे इन सभी केसीसी आवेदनों को निष्पादन करने की दिशा में कार्य करें। केसीसी आवेदनों में यदि कोई त्रुटि है, तो उसे जिला कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन के सहयोग से ठीक करवाने हेतु विशेष बीएलबीसी बैठक आयोजित कर उसमें चर्चा करें।
- इसी प्रकार, उन्होने डेयरी एवं फिशेरी किसानों को केसीसी जारी करने के आंकड़ों के संबंध मे बताया कि बैंकों द्वारा आवेदन स्वीकृति की तुलना में Reject किए जाने वाले आवेदनों की संख्या बहुत अधिक है, जो एक चिंता का विषय है।
- इसी क्रम में, उन्होने एग्री इन्फ्रा फ़ंड की उपलब्धि की चर्चा करते हुये बताया कि भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में झारखंड राज्य की उपलब्धि नगण्य है, जबकि राज्य का लक्ष्य काफी ज्यादा है। उन्होने कहा कि गत वर्ष राज्य के मुख्य सचिव महोदय, द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एग्री इन्फ्रा फ़ंड योजना में कम से कम एक ऋण स्वीकृति का लक्ष्य दिया गया था, किन्तु उपलब्धि बहुत खराब रही है । उन्होने बैंकों / LDM / नाबार्ड से इस योजना में अधिक से अधिक आवेदन सृजित करने एवं स्वीकृत करने को कहा।
- उन्होने बैंकों से FPOs एवं Horticulture में फ़ाइनेंस करने के लिए बैंको से अनुरोध किया। साथ ही साथ उन्होने बैंकों को सरकारी योजनाओं के फ़ाइनेंस में विशेष ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया, जिससे राज्य का सीडी ratio में सुधार तथा राज्य के गरीबों को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी।
- अंत में, उन्होने बताया कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के किसानों को "**बिरसा किसान**" के रूप में प्रचारित किया जाएगा। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि वे किसानों को ऋण देते समय उनके स्वीकृति-पत्र में किसान के स्थान पर बिरसा किसान लिखा जाए, जिससे राज्य के किसानों को स्थानीय महत्ता बतायी जा सके।
- उन्होने विशेष सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार श्रीमती दीप्ती जयराज के अनुरोध पर अपने विभाग को निर्देश दिया कि जिला प्रशासन द्वारा सृजित केसीसी आवेदनों की बैंकवार-शाखावार सूची उपलब्ध कराएं, जिससे इनकी निगरानी एवं समीक्षा नियमित रूप से की जा सके।

<u>श्रीमति नैन्सी सहाय, सीईओ, जेएसएलपीएस,झारखंड का सम्बोधन</u>

- श्रीमति नैन्सी सहाय ने सभा को संबोधित करने हेतु आग्रह किया कि इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम तिमाही में कुल वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 29% एसएचजी आवेदनों को ऋण वितरित किये जा चुके हैं। इस दौरान बैंकों द्वारा कुल 36,697 SHG Groups का क्रेडिट लिंकेज करते हुये कुल रु 200.74 करोड़ वितरित किया गया है। उन्होने बैंकों से अनुरोध किया कि सितम्बर महीने तक हमें कुल वार्षिक लक्ष्य का 60% उपलब्धि हासिल करने हेतु प्रयास करना चाहिए।
- उन्होने सभा को जानकारी दी कि कुल 2.42 लाख एसएचजी के बचत खाता खोले गए हैं, जिनमें से अभी तक कुल 1.53 लाख एसएचजी बचत खातों की क्रेडिट लिंकेज किया जा चुका है एवं 15 जुलाई तक की स्थिति के अनुसार कुल 88,843 SHG बचत खातों को क्रेडिट लिंकेज किया जाना बाकी है।
- उन्होने आगे कहा कि कुछ बैंकों द्वारा काफी संख्या में एसएचजी ग्रुप की महिलाओं को बैंक बीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होने जानकारी दी कि जेएसएलपीएस द्वारा कुल 3,540 एसएचजी ग्रुप की महिलाओं को Digi-Pay एजेंट का प्रशिक्षण दिया गया है, जो बैंक बीसी एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। अत: उन्होने सभी बैंकों से अनुरोध किया कि राज्य के प्रत्येक ग्राम-पंचायत में इन एसएचजी ग्रुप की महिलाओं को बैंक बीसी नियुक्त किया जाए।
- उन्होने सभा को जानकारी दी कि MoRD, भारत सरकार द्वारा सभी एसएचजी ग्रुप की महिलाओं एवं उनके पति को बैंकों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जाना है। झारखंड में कुल 33 लाख महिलाएं 2.63 SHG Groups से जुड़े हैं, जिसमें सभी को पीएमएसबीवाई तथा कम से कम 70% लोगों को पीएमजेजेबीवाई से जोड़ना है। साथ ही साथ कुल Eligible का 10-15% लोगों को APY में Enrollment भी करना है। उन्होने कहा कि कुल लक्ष्य का 60% उपलब्धि सितम्बर महीने तक करनी है, इसके लिए JSLPS द्वारा 07/08/2021 से 07/09/2021 तक सभी जिलों में "**बीमा कराएँ अभियान**" चलाया जा रहा है। उन्होने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी बैंकों को जेएसएलपीएस के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया है।
- उन्होने आगे जानकारी दी कि राज्य के विभिन्न बैंकों के पास पीएमएसबीवाई एवं पीएमजेजेबीवाई के लगभग 80 Claim under Process हैं, जिनका निष्पादन बैंकों द्वारा किया जाना है। उन्होने बताया कि SBI-13, JRGB-18, BOI-32, CANARA Bank-8, IOB-4, BOB-2, PNB-1 एवं UCO Bank-1 के पास Claim Satlement under process है। उन्होने संबन्धित बैंकों से अनुरोध किया कि इनका निष्पादन यथाशीघ्र किए जाने का अनुरोध किया।
- अंतमें, उन्होने बताया कि SHG खातों में बैंकों के एनपीए के संबंध में राज्य में कुल SHG Groups का क्रेडिट लिंकेज का 4.47% एनपीए है तथा उनका लक्ष्य है कि इसे Oct. 2021 तक 2.00% तक लाया जा सके एवं इसके लिए JSLPS बैंकों के साथ कार्य कर रहा है।

<u>व्यवसायिक सत्र की परिचर्चा</u>

- इस सत्र में बैंकों द्वारा SLBC पोर्टल पर Standardized सिस्टम के तहत डाटा FLOW पर चर्चा के दौरान एसएलबीसी द्वारा जानकारी दी गई कि जून, 2021 तिमाही हेतु लक्ष्मी विलास बैंक (डीबीएस) के द्वारा डाटा अपलोड/उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिसके प्रत्युतर में लक्ष्मी विलास बैंक (डीबीएस) के प्रतिनिधि श्री मनीष सिन्हा ने जानकारी दी कि उनके प्रधान कार्यालय द्वारा दिये गए डाटा में ब्लॉक कोड में गलती होने के कारण डाटा एसएलबीसी को नहीं दिया जा सका।

- उपरोक्तविषय पर आरबीआई द्वारा कहा गया कि भविष्य में यदि किसी बैंक को द्वारा एसएलबीसी की तिमाही बैठक के लिए डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उन्हे बैठक में आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डाटा के बिना समीक्षा बैठक की प्रासंगिकता नहीं हो सकती है।
- एसएलबीसी बैठक के व्यवसायिक सत्र में चर्चा के दौरान आईएफ़सीआई की प्रतिनिधि श्रीमती बरखा छाबरा ने जानकारी दी कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च, 2015 में आईएफसीआई को "अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना" के कार्यान्वन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में पदनामित किया है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के उद्यमियों को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं अर्थात् बैंकों की मार्फत ऋण वृद्धि गांरटी से वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जाति के बीच उद्यमीयता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति समुदाय के उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से 15 लाख से 15 करोड़ तक ऋण पर आईएफसीआई द्वारा गारंटी कवर दिया जाता है। उन्होने आगे जानकारी दी कि इस योजना की विस्तृत जानकारी आईएफसीआई के website से प्राप्त किया जा सकता है।
- एसएलबीसी बैठक के व्यवसायिक सत्र में Digital Banking / Less Cash पर चर्चा के दौरान NPCI के प्रतिनिधि श्री धीरेंद्र सिंह चौहान ने सभा को राज्य डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु NPCI के पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। उन्होने जानकारी दिया कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सभी Street Vendors को, जिन्हे बैंक से रु 10,000 का ऋण दिया गया है, उन्हे डिजिटल लेन-देन के लिए QR Code दिया जा रहा है। उन्होने व्यवसायियों को POS मशीन में लगने वाले चार्ज से बचने के लिए QR Code एवं UPI को अपनाने की सलाह दी। उन्होने राज्य के 19 Aspirational Districts एवं Digital District में भी डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने में अपना सहयोग देने की बात कही।
- इस संबंध में, आरबीआई के महाप्रबंधक श्री संजीव सिन्हा ने एसएलबीसी को सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों की एनपीसीआई के साथ एक Online Awareness Programme आयोजित करने के लिए सलाह दिया, जिससे वे इस जानकारी को जिलास्तर पर शाखाओं तक पहुंचा सकें।

<u>श्रीमती दीप्ती जयराज, विशेष सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार का सम्बोधन</u>

- एसएलबीसी बैठक के व्यवसायिक सत्र के उपरांत विशेष सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार श्रीमती दीप्ती जयराज को सभा को संबोधित करने हेतु आग्रह किया गया। श्रीमती दीप्ती जयराज ने सभा को संबोधित करते हुये कहा कि रामगढ़ RSETI भवन निर्माण हेतु आबंटित भूमि में आ रही बाधा को दूर करने के लिए वे स्वयं रामगढ़ जिला उपायुक्त से बात कर रही हैं एवं आशा है कि बहुत जल्दी ही इसका समाधान हो जाएगा, जिससे भवन निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।
- उन्होने एसएलबीसी से डिजिटल ई-स्टांपिंग की प्रगति रिपोर्ट साझा करने को कहा और सभी बैंकों से अनुरोध किया कि सभी बैंक अपने लोन डॉकयुमेंट की डिजिटल ई-स्टांपिंग शुरू करें। उन्होने एसएलबीसी को SLBC

  पोर्टल पर Standardized सिस्टम के तहत डाटा अपलोडिंग शुरू करने के लिए बधाई दिया। साथ ही साथ उन्होने एसबीआई को सलाह दी कि राज्य के सबसे बड़े बैंक होने के नाते एसएलबीसी को दिये जाने वाले डाटा की सत्यता के प्रति उनकी सबसे ज्यादा ज़िम्मेदारी है एवं उन्हे इसपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
- उन्होने राज्य में अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में अच्छा कार्य करने के लिए एसएलबीसी एवं सभी बैंकों को बधाई दिया तथा आशा व्यक्त किया कि इस वित्तीय वर्ष में भी सभी बैंक अच्छा कार्य करेंगें।

- उन्होने सभा को जानकारी दी कि राज्य सरकार Government Business के लिए दो बैंकों का चयन कर रही है, जिसका आधार राज्य में उनका ग्रामीण शाखा नेटवर्क, बीसी नेटवर्क, शिक्षा ऋण, आवास ऋण एवं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अतर्गत उपलब्धि रहेगी। अत: उन्होने सभी बैंकों को इस क्षेत्र में विशेष प्रयास करने हेतु सलाह दी। उन्होने बैंकों को Interest Subvention Scheme वाले सरकारी योजनाओं का विशेष प्रचार-प्रसार करने की सलाह दी।

आरबीआई के महाप्रबंधक ने एसएलबीसी से अनुरोध किया कि वे भारतीय स्टेट बैंक से उनके द्वारा दिये गए डाटा की सत्यता के बारे में जानकारी मांगे? इसके जवाब में एसबीआई से एजीएम श्री रूपेश कुमार ने सदन को जानकारी दी कि उनके कुछ ऋण खाते, जो Sanctioned at Out side Jharkhand but Credit Utilised in Jharkhand के वर्ग में आता है, उसमें जून तिमाही में रु 5,000 करोड़ की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके कारण उनके कुल अग्रिम में गिरावट आई है। उन्होने ये खाते तेल क्षेत्र (IOC, HPCL) के होने की जानकारी दी एवं उनके द्वारा एसएलबीसी पोर्टल पर अपलोड किए गए डाटा पूर्णतया: बैंक के सीबीएस पोर्टल से लिया गया है।

अंत में, पंजाब नेशनल बैंक के उपमहाप्रबंधक श्री दीपक श्रीवास्तव ने एसएलबीसी की 76वीं बैठक में उपस्थित सभी स्टेक होल्डेर्स का धन्यवाद ज्ञापन किया।

(उद्दालक भट्टाचार्य)
महाप्रबंधक,रा. स्त. बै. स.

संलग्न :-

1. **उपस्थिति**
2. **ATR**
3. **जून 2021 तिमाही के विभिन्न उपसमितियों के बैठक का कार्यवृत**

LIST OF PARTICIPANTS IN 76th STATE LEVEL BANKERS' COMMITTEE, JHARKHAND (MEETING HELD ON 11.08.2021)			
S.N	**NAME OF PARTICIPANTS/ ORAGNISATION**	**DESINGNATION**	**BANK/DEPARTMENT**
1	SRI SANJIV SINHA	GENERAL MANAGER (oic)	RESERVE BANK OF INDIA
2	DR. GOPA KUMARAN NAIR	CHIEF GENERAL MANAGER	NABARD
3	SRI RICHARD ALOK EKKA	ASST. GENERAL MANAGER	RESERVE BANK OF INDIA
4	SRI UDDALOK BHATTACHARYA	GENERAL MANAGER	SLBC JHARKHAND
5	SRI GANESH TOPPO	DY. GENERAL MANAGER	SLBC JHARKHAND
6	SMT NANCY SAHAY	SECRETARY	JSLPS
7	GOVT. OF JHARKAHND	SECRETARY	DEPT. OF INDUSTRY
8	GOVT. OF JHARKAHND	DY. DIRECTOR	DEPT. OF AGRICULTURE
9	MRS DIPTHI JAYARAJ	SEPECIAL SECRETARY	IFPI DEPARTMENT
10	GOVT. OF JHARKAHND	SECRETARY	DEPT. OF FINANCE
11	SRI ASHIS DONGARE	ASST. GENERAL MANAGER	PFRDA
12	SRI DHIRENDRA KUMAR CHOUHAN	REPRESENTATIVE	NPCI
13	SRI ANIL KUMAR	STATE NODAL OFFICER	RSETI, JSLPS
14	GOVT. OF INDIA	REPRESENTATIVE	MSME DI
15	GOVT. OF INDIA	REPRESENTATIVE	NATIONAL SC ST HUB RANCHI
16	GOVT. OF INDIA	REPRESENTATIVE	CSC
17	GOVT. OF INDIA	REPRESENTATIVE	STATE OFFICE KVIC
18	GOVT. OF INDIA	REPRESENTATIVE	NATIONAL HOUSING BOARD
19	PSB	DY. GENERAL MANAGER	UCO BANK
20	PSB	ZONAL MANAGER	INDIAN BANK
21	PSB	REGIONAL MANAGER	CENTRAL BANK OF INDIA
22	PSB	DY. REGIONAL MANAGER	BANK OF BARODA
23	PSB	DY. GENERAL MANAGER	UNION BANK OF INDIA
24	PSB	DY. ZONAL MANAGER	BANK OF INDIA
25	PSB	CHAIRMAN	JHARKHAND STATE COOPERATIVE BANK
26	PSB	ASST. GENERAL MANAGER	JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK
27	PSB	ASST. GENERAL MANAGER	CANARA BANK
28	PSB	BRANCH MANAGER	BANK OF MAHARASTRA
29	PSB	CHIEF REGIONAL MANAGER	INDIAN OVERSEAS BANK
30	PSB	CHIEF MANAGER	PUNJAB NATIONAL BANK
31	PSB	DY. GENERAL MANAGER	STATE BANK OF INDIA
32	PSB	CHIEF MANAGER	PUNJAB & SIND BANK
33	PVT BANK	ASST VICE PRESIDENT	YES BANK
34	PVT BANK	REGIONAL HEAD	IDBI BANK
35	PVT BANK	ASST BRANCH MANAGER	KARNATAKA BANK
36	PVT BANK	SENIOR MANAGER	SOUTH INDIAN BANK
37	PVT BANK	CLUSTER HEAD	BANDHAN BANK
38	PVT BANK	SENIOR MANAGER	FEDERAL BANK
39	PVT BANK	ASST BRANCH MANAGER	KARUR VAISYA BANK
40	PVT BANK	BRANCH HEAD	DBS BANK
41	PVT BANK	REPRESENTATIVE	AXIS BANK
42	PVT BANK	REPRESENTATIVE	DCCB
43	PVT BANK	REPRESENTATIVE	HDFC BANK
44	PVT BANK	REPRESENTATIVE	ICICI BANK
45	PVT BANK	REPRESENTATIVE	IDFC FISRT BANK
46	PVT BANK	REPRESENTATIVE	INDUSIND BANK
47	PVT BANK	REPRESENTATIVE	JAMMU & KASHMIR BANK LTD
48	PVT BANK	REPRESENTATIVE	KOTAK MAHINDRA BANK
49	SFB	STATE HEAD	AIRTEL PAYMENT BANK
50	SFB	ZONAL HEAD	UTKARSH SMALL FINANCE BANK
51	SFB	REGIONAL HEAD	JANA SMALL FINANCE BANK
52	SFB	MANAGER	FINO PAYMENT BANK
53	SFB	ASST GENERAL MANAGER	INDIA POST PAYMENT BANK
54	SFB	ZONAL HEAD	UJJIVAN SMALL FINANCE BANK
55	SFB	ASST MANAGER	EASF BANK
56	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	LOHARDAGA

S.N	NAME OF PARTICIPANTS/ ORAGNISATION	DESINGNATION	BANK/DEPARTMENT
57	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	CHATRA
58	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	DUMKA
59	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	SARAIKELA-KHARSAWAN
60	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	GODDA
61	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	RANCHI
62	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	KODERMA
63	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	SIMDEGA
64	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	JAMTARA
65	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	WEST SINGHBHUM
66	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	RAMGARH
67	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	GUMLA
68	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	KHUNTI
69	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	EAST SINGHBHUM
70	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	DEOGHAR
71	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	DHANBAD
72	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	GARHWA
73	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	BOKARO
74	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	HAZARIBAGH
75	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	GIRIDIH
76	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	LATEHAR
77	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	PAKUR
78	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	PALAMAU
79	LDM	LEAD DISTRICT MANAGER	SAHEBGANJ

76 वी. एसएलबीसी के बैठक के दौरान प्रमुख विंदुओ पर अपेक्षित कृत कार्यवाही रिपोर्ट

क्रम संख्या	विषय	विवरण	कृत कार्यवाही
01	किसान क्रेडिट कार्ड	राज्य सरकार के सहयोग मे दिनांक 12 जुलाई 2021 से किसान क्रेडिट कार्ड ड्राइव के तहत 6.96 लाख आवेदन सृजित किए गए, जिनमे 1.57 लाख से अधिक आवेदन बैंको द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। पेंडिंग एप्लिकेशन का निष्पादन NABARD द्वारा जारी FAQ का संदर्भ लेकर प्रमुखता से करना है। **(एक्शन: सभी बैंक)** Secretary, Agriculture, GoJ के दिशा निर्देशानुसार वैसे केसीसी आवेदन जो कि बैंको द्वारा कुछ कमियो के कारण वापिस किए गए हैं उन्हे निदेशक, डेयरी एवं फिशेरी कार्यालय द्वारा खामियों को दूर करते हुए पुनः बैंक मे जमा करे। **(एक्शन: निदेशक, Dairy, Fisheries, JMF)** राज्य सरकार द्वारा VLW एवं कृषक मित्र की सेवाएँ बैंक शाखाओं को प्राप्त हो रही हैं, जिससे कृषि ऋण वितरण में पहले की अपेक्षा प्रगति हो रही है। साथ ही साथ प्रखण्ड स्तर पर special BLBC करते हुए local level के stakeholders के बीच KCC ऋण वितरण की समीक्षा की जानी चाहिए। **(एक्शन: सभी एलडीएम)** सभा को जानकारी दी गयी कि राज्य में 30 लाख पीएम किसान के लाभुक हैं तथा राज्य में लगभग 50 लाख से ज्यादा किसान हैं। राज्य में जून, 2021 तक बैंकों की रिपोर्टिंग के अनुसार 13 लाख केसीसी जारी किये गए है। साथ ही राज्य सरकार ने 10 लाख केसीसी आवेदन सृजित करने का तत्काल लक्ष्य रखा है जिससे राज्य के सभी किसानो को केसीसी कार्ड जारी किये जाने हेतु मार्ग प्रशस्त हो। **(एक्शन: सभी बैंक)**	
02	CD रेशियो, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों मे गिरावट	पिछली तिमाही की अपेक्षा विभिन्न पहलुओं (CD Ratio, Priority Sector Advance) मे गिरावट आने पर चिंता जाहिर की। ऋण जमा अनुपात के निरंतर गिरते हुए आँकड़ो पर चिंता जाहिर करते हुए सभा को जानकारी दी कि जून, तिमाही में राज्य का 2021 CD Ratio37.04 % तक आ चुका है, जो कि पिछली मार्च, तिमाही के 2021CD Ratio42.43 % से काफी नीचे	

		है। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के जून 21-2020,2020 तिमाही में राज्य का CD Ratio54.94 % था। **(एक्शन: सभी बैंक,एलडीएम एवं नाबार्ड)** राज्य के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण प्रवाह में 30% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में ज्यादा शाखाओ वाले बैंकों का प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण में कम Share होने पर चिंता व्यक्त की गयी। **(एक्शन: सभी बैंक,एलडीएम)**	
03	पीएम स्वनिधि योजना मे बैंको का प्रदर्शन	पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत बैंको को 80,000 आवेदन का लक्ष्य मार्च 2022 तक दिया गया है जिसके मापेक्ष 44,820 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिममे 55% से अधिक आवेदनों की स्वीकृति की जा चुकी हैं साथ ही साथ **"स्वनिधि से समृद्धि:"** campaign के तहत रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में कैंप का आयोजन कर PM SVANidhi के ऋणी एवं उनके परिवार के सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं मे भी Coverage किया जाना है। **(एक्शन: सभी बैंक,संबन्धितएलडीएम)**	
04	e-Stamping सुविधा	e-Stamping के संबंध में जानकारी दी गयी कि राज्य–सरकार तथा वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार के सहयोग से झारखंड राज्य में e-Stamping को लागू किया जा चुका है। हालांकि SLBC को अभी तक केवल तीन बैंको द्वारा ही इसके उपयोग की जानकारी प्रदान की गयी है। **(एक्शन: सभी बैंक)**	
05	18 बैंको द्वारा SWOT analysis का प्रष्तुतीकरण	राज्य मे जिन बैंकों द्वारा पिछले वर्ष ACP का लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ था वैसे 18 बैंको द्वारा अपने बैंक का SWOT Analysis का प्रस्तुतीकरण वर्तमान महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक श्री संजीव सिन्हा तथा रा॰स्त॰बै॰म॰ के समक्ष किया गया जिममे अपने बैंक की प्रगति बढ़ाने हेतु सुझाव प्राप्त हुए तदनुसार महाप्रबंधक द्वारा बैंकों को लक्ष्य भी प्रदान किये गए। उक्त बैंकों को	

76 वी. एसएलबीसी के बैठक के दौरान प्रमुख विंदुओ पर अपेक्षित कृत कार्यवाही रिपोर्ट

		अपनी प्रगति पुनः महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक तथा रा०स्त०बै०स० के समक्ष प्रस्तुत करनी है। **(एक्शन: संबन्धित सभी बैंक)**	
06	Cyber Incident reporting mechanism	आरबीआई के निर्देशानुसार राज्य में Cyber Incident reporting mechanism, Karnataka Model के आधार पर लागू करने के लिए राज्य के Major Banks एवं राज्य पुलिस विभाग के साथ विस्तृत चर्चा की गयी एवं झारखंड राज्य के लिए एक मॉडल तैयार किया जाना है जो कि राज्य मे लागू किया जा सके। साइबर फ्रॉड को राज्य के सभी स्टेक होल्डेर्स के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या बताई गयी। साइबर फ्रॉड के रोकथाम हेतु Electronic Architecture सृजित करने का सुझाव दिया, जहाँ पुलिस एवं बैंक officials ऑनलाइन जानकारी साझा कर सकेंगें एवं संबन्धित विभाग द्वारा समय पर पूर्व-नियोजित कार्यवाही करते हुये खाताधारकों के जोखिम को कम किया जा सकेगा। **(एक्शन: सभी बैंक)**	
07	Online Charge Creation Facility for Banks	Punjab National Bank, Canara Bank, Union Bank of India की विशेष समिति द्वारा online Charge Creation के मुद्दे पर बनाए गए ड्राफ्ट पर राज्य के Major Banks के साथ चर्चा की गयी साथ ही साथ राज्य के revenue department के साथ चर्चा कर फ़ाइनल ड्राफ्ट बनाया गया। **Land Charge Creation By Bank** के संबंध में राज्य सरकार के सहयोग की अपेक्षा की गयी। उपरोक्त व्यवस्था मे निश्चित तौर पर बैंकों को वास्तविक भूस्वामी को ऋण वितरण करने में सुविधा मिलेगी। Digitilisation and Updation of Land Record के कारण राज्य के कृषि ऋण प्रवाह में भी काफी तेजी आएगी। **(एक्शन: राज्य सरकार)**	
08	सर्टिफिकेट ऑफिसर कि नियुक्ति	राज्य सरकार द्वारा अब तक दस जिलों में सर्टिफिकेट ऑफिसर कि नियुक्ति की जा चुकी है, हालाँकि अन्य	

76 वी. एसएलबीसी के बैठक के दौरान प्रमुख विंदुओ पर अपेक्षित कृत कार्यवाही रिपोर्ट

		जिलों में अविलंब नियुक्ति हेतु प्रयास करने की आवश्यकता बतायी। **(एक्शन: राज्य सरकार)**	
09	100% Digitisation of East Singhbhum and Ranchi District	East Singhbhum जिले में 99.37% digitally coverage किया जा चुका है इस कार्य मे प्रोत्साहित होते हुए RBI के दिशानिर्देशानुमार Ranchi जिले को भी Digitally आच्छादित करने हेतु अभियान शुरू किया गया है। **(एक्शन: संबन्धित एलडीएम एवं बैंक)**	
10	SC / ST को ऋण प्रवाह	झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या का 12.08% Scheduled Caste (SC) and 26.21% Scheduled Tribe (ST) हैं जबकि राज्य के कुल ऋण प्रवाह का केवल 9.09% ही एसटी/एससी वर्ग को दिया गया है, जो कि एक चिंता का विषय है। **(एक्शन: सभी बैंक)**	
11	Government Sponsored Scheme में NPA की स्थिति	राज्य में बैंकों का NPA पिछली वित्तीय वर्ष 2020-21 के जून तिमाही से 5.22% बढ़कर जून, 2021 तिमाही में 9.82% हो गया है, यह काफी विचारणीय विषय है। NPA के आँकड़ो में अपेक्षाकृत तीव्र वृद्धि के कारण राज्य में बैंकों द्वारा दिये गए Government Sponsored Scheme के ऋण में भी दर्ज की गई है। **(एक्शन: सभी बैंक, संबन्धित विभाग)**	
12	कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह	राज्य में खरीफ के मौसम में राज्य में किसानों को पूंजी की आवश्यकता के मद्देनजर बैंकों से आग्रह किया गया कि कृषि क्षेत्र में ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को तत्परता दिखानी चाहिये। **(एक्शन: सभी बैंक, राज्य सरकार)**	
13	कोविड 19-महामारी के कारण राज्य में रोजगार	कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में रोजगार की कमी होने की बात कही गयी, हालांकि रिर्वस माइग्रेशन के कारण बाहर से आए मजदूर दूसरे स्टेट में वापस भी लौट रहे हैं। इस विषय पर पलायन रोकने हेतु अपने	

	सृजन हेतु ऋण की उपलब्धता	राज्य मे रोजगार शुरू करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता बतायी। भारत सरकार की Agri Infra fund के अंतर्गत Horticulture के क्षेत्र में ऋण प्रवाह हेतु बैंकों को प्रोत्साहन देने की बात कही गयी। **(एक्शन: सभी बैंक)**	
14	ग्रामीण शाखाओं मे कमी	इस तिमाही मे बैंकों द्वारा Rationalisation of Branches के कारण राज्य में 43 ग्रामीण शाखाएँ कम होने पर आरबीआई ने चिंता जाहीर करते हुए बताया कि बैंको को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बैंकिंग सेवाए सुनिश्चित करनी चाहिए। **(एक्शन: सभी बैंक)**	
15	सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में Low Sanction, High rejections and Huge Pendency के संबंध मे	सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में Low Sanction, High rejections and Huge Pendency के संबंध में सलाह दी गयी कि एसएलबीसी की प्रस्तावित बैठक के पहले बैंक एवं प्रायोजित एजेंसी को एक साथ बैठक कर आवेदनों के rejection के कारणों पर परिचर्चा के साथ ही साथ सुधार करने के उपायों पर भी चर्चा करनी चाहिए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की खामियाँ आवेदनों में ना हो तथा बैंक द्वारा ऋण प्रवाह में भी तेजी आएगी। **(एक्शन: सभी बैंक/ संबन्धित एजेंसी)**	
16	Small Finance Bank का प्रदर्शन	जून तिमाही डाटा के अनुसार Small Finance Banks के प्रदर्शन पर आरबीआई के द्वारा चिंता जाहीर की गयी एवं बताया गया कि प्रदर्शन मे सुधार की आवश्यकता है तथा विस्तार की काफी संभावनाएं हैं। **(एक्शन-समस्त Small Finance Bank)**	
17	SHG एवं CGFMU के नवीनतम दिशानिर्देश	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा Collateral Free SHG Finance एवं Loan under Credit Guarantee Fund for Micro Units के लिए नवीनतम दिशा-निर्देश जारी किये है। जिन्हे ममस्त बैंक को अनुपालन करना है। **(एक्शन-सभी सदस्य बैंक)**	
18	आरबीआई द्वारा बैंकों पर System of Monetary Penalty	आरबीआई द्वारा बैंकों पर System of Monetary Penalty के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया गया है, अतः बैंको को एटीएम मे Cash की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।	

76 वी. एसएलबीसी के बैठक के दौरान प्रमुख विंदुओ पर अपेक्षित कृत कार्यवाही रिपोर्ट

		(एक्शन-सभी सदस्य बैंक)	
19	APY एनरोलमेंट	श्री आशीष डोंगरे ने एसएलबीसी झारखंड एवं सभी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2020-21 में APY के अंतर्गत पूरे देश में चौथा स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई दी। उन्होने इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में जुलाई तक APY एनरोल्लमेंट मे 35% उपलब्धि होने की जानकारी दी। श्री डोंगरे ने पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बरौदा एवं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को APY enrollment में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बतायी। **(एक्शन-पीएनबी,इंडियन,BOB,यूनियन बैंक)**	
		PFRDA द्वारा सभी राज्यों के एनआरएलएम से जुड़े SHG Group के सदस्यों को APY enrollment के लिए झारखंड सहित सभी राज्य के एनआरएलएम को पत्र लिखा है, जिससे राज्य में APY enrollment में तेजी आने की संभावना है। **(एक्शन-समस्त बैंक,JSLPS)** PFRDA द्वारा चलाये जा रहे APY Citizen Choice Campaign की जानकारी देते हुए एसएलबीसी एवं सभी बैंकों से अनुरोध किया कि इस अवधि में अधिक से अधिक APY Enrollment करने हेतु प्रयास करें। **(एक्शन- समस्त बैंक)** PFRDA ने राज्य के एनआरएलएम टीम तथा एसएलबीमी के साथ पीएफ़आरडीए की एक संयुक्त बैठक कराने हेतु भी अनुरोध किया। **(एक्शन- NRLM,PFRDA,SLBC)**	
20	एग्री इन्फ्रा फ़ंड की उपलब्धि	एग्री इन्फ्रा फ़ंड की उपलब्धि की चर्चा करते हुये बताया गया कि भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना में झारखंड राज्य की उपलब्धि नगण्य है, जबकि राज्य का लक्ष्य काफी ज्यादा है। गत वर्ष राज्य के मुख्य सचिव महोदय, द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एग्री इन्फ्रा फ़ंड योजना में कम से कम एक ऋण स्वीकृति का लक्ष्य दिया गया था, किन्तु उपलब्धि बहुत खराब रही है। सचिव कृषि ने बैंकों / LDM / नाबार्ड से इस योजना में	

		अधिक से अधिक आवेदन सृजित एवं स्वीकृत करने को कहा। **(एक्शन-समस्त बैंक, LDM,नाबार्ड)**	
21	FPOs एवं Horticulture सेक्टर में फ़ाइनेंस	सभा ने बैंकों से FPOs एवं Horticulture में फ़ाइनेंस करने के लिए अनुरोध किया। साथ ही साथ बैंकों को सरकारी योजनाओं के फ़ाइनेंस में विशेष ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया गया, जिससे राज्य का सीडी Ratio में सुधार तथा राज्य के गरीबों को आर्थिक स्वतंत्रता मिल सकेगी। **(एक्शन-समस्त बैंक)**	
22	किसानों को "**बिरसा किसान**" क्रेडिट कार्ड प्रदान करना	राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के किसानों को "**बिरसा किसान**" के रूप में प्रचारित किया जाएगा। उन्होंने बैंकों मे अनुरोध किया कि किसानों को ऋण देते समय उनके स्वीकृति-पत्र में किसान के स्थान पर बिरसा किसान लिखा जाए, जिससे राज्य के किसानों को स्थानीय महत्ता बतायी जा सके। **(एक्शन-समस्त बैंक)**	
23	सृजित केसीसी आवेदनों की बैंकवार- शाखावार सूची उपलब्ध कराने के विषय मे	विशेष सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार श्रीमती दीपी जयराज के अनुरोध पर कृषि सचिव ने विभाग को सृजित केसीसी आवेदनों की बैंकवार-शाखावार सूची उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया, जिससे आवेदनों की निगरानी एवं समीक्षा नियमित रूप से की जा सके। **(एक्शन-कृषि विभाग)**	
24	एसएचजी मे ऋण की समीक्षा	श्रीमति नैन्सी सहाय ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम तिमाही में कुल वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध 29% एसएचजी आवेदनों को ऋण वितरित किये जा चुके हैं। इस दौरान बैंकों द्वारा कुल 36,697 SHG Groups का क्रेडिट लिंकेज करते हुये कुल रु 200.74 करोड़ वितरित किया गया है। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि सितम्बर महीने तक हमें कुल वार्षिक लक्ष्य का 60% उपलब्धि हासिल करने हेतु प्रयास करना चाहिए। **(एक्शन-समस्त बैंक)**	
25	SHG क्रेडिट लिंकेज	सभा को जानकारी दी गयी कि राज्य में कुल 2.42 लाख एसएचजी के बचत खाता खोले गए हैं, जिनमें से अभी तक कुल 1.53 लाख एसएचजी बचत खातों की क्रेडिट लिंकेज किया जा चुका है एवं 15 जुलाई तक की स्थिति	

76 वी. एसएलबीसी के बैठक के दौरान प्रमुख विंदुओ पर अपेक्षित कृत कार्यवाही रिपोर्ट

		के अनुसार कुल 88,843 SHG बचत खातों को क्रेडिट लिंकेज किया जाना बाकी है। **(एक्शन-समस्त बैंक)**	
26	एसएचजी ग्रुप की महिलाओं को बैंक बीसी नियुक्ति	जेएसएलपीएस द्वारा कुल 3,540 एसएचजी ग्रुप की महिलाओं को Digi-Pay एजेंट का प्रशिक्षण दिया गया है, जो बैंक बीसी एजेंट के रूप में कार्य कर सकते हैं। अत: सभी बैंकों से अनुरोध किया गया कि राज्य के प्रत्येक ग्राम-पंचायत में इन एसएचजी ग्रुप की महिलाओं को बैंक बीसी नियुक्त किया जाए। **(एक्शन-समस्त बैंक)**	
27	एसएचजी ग्रुप की महिलाओं एवं उनके पति को बैंकों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जाना	CEO JSLPS ने सभा को जानकारी दी कि MoRD, भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी एसएचजी ग्रुप की महिलाओं एवं उनके पति को बैंकों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़ा जाना है। झारखंड में कुल 33 लाख महिलाएं 2.63 लाख SHG Groups से जुड़ी हैं, जिसमें सभी को पीएमएसबीवाई तथा कम से कम 70% लोगों को पीएमजेजेबीवाई से जोड़ना है। साथ ही साथ कुल Eligible के 10-15% लोगों को APY में Enrollment भी करना है। उन्होने कहा कि कुल लक्ष्य का 60% उपलब्धि सितम्बर महीने तक करनी है, इसके लिए JSLPS द्वारा 07/08/2021 से 07/09/2021 तक सभी जिलों में **"बीमा कराएँ अभियान"** चलाया जा रहा है। उन्होने इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी बैंकों को जेएसएलपीएस के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया है। **(एक्शन-समस्त बैंक)**	
28	पीएमएसबीवाई एवं पीएमजेजेबीवाई के Claim की प्रोसेसिंग	JSLPS द्वारा जानकारी दी गयी कि राज्य के विभिन्न बैंकों के पास पीएमएसबीवाई एवं पीएमजेजेबीवाई के लगभग 80 Claim under Process हैं, जिनका निष्पादन बैंकों द्वारा किया जाना है। उन्होने बताया कि SBI-13, JRGB-18, BOI-32, CANARA Bank-8, IOB-4, BOB-2, PNB-1 एवं UCO Bank-1 के पास Claim Settlement under process है। उन्होने संबन्धित बैंकों से अनुरोध किया कि इनका निष्पादन यथाशीघ्र किए जाने का अनुरोध किया। **(एक्शन-संबन्धित बैंक)**	

29	SHG खातों में बैंकों के एनपीए	JSLPS ने बताया कि बैंकों में राज्य में कुल SHG Groups का क्रेडिट लिंकेज का 4.47% एनपीए है तथा उनका लक्ष्य है कि इसे Oct 2021 तक 2.00% तक लाया जा सके एवं इसके लिए JSLPS बैंकों के साथ कार्य कर रहा है। **(एक्शन-समस्त बैंक, JSLPS)**	
30	SLBC पोर्टल पर Standardized सिस्टम के तहत डाटा FLOW का क्रियान्वयन	बैंकों द्वारा SLBC पोर्टल पर Standardized सिस्टम के तहत डाटा FLOW पर चर्चा के दौरान एसएलबीसी द्वारा जानकारी दी गई कि जून, 2021 तिमाही हेतु लक्ष्मी विलास बैंक (डीबीएस) के द्वारा डाटा अपलोड/उपलब्ध नहीं कराया गया था, जिसके प्रत्युतर में लक्ष्मी विलास बैंक (डीबीएस) के प्रतिनिधि श्री मनीष सिन्हा ने जानकारी दी कि उनके प्रधान कार्यालय द्वारा दिये गए डाटा में ब्लॉक कोड में गलती होने के कारण डाटा एसएलबीसी को नहीं दिया जा सका। उपरोक्तविषय पर आरबीआई द्वारा कहा गया कि भविष्य में यदि किसी बैंक को द्वारा एसएलबीसी की तिमाही बैठक के लिए डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उन्हे बैठक में आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डाटा के बिना समीक्षा बैठक की प्रासंगिकता नहीं हो सकती है। **(एक्शन-समस्त बैंक,DBS बैंक)**	
31	अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना" का कार्यान्वन	एसएलबीसी बैठक के व्यवसायिक सत्र में चर्चा के दौरान आईएफ़सीआई की प्रतिनिधि श्रीमती बरखा छाबरा ने जानकारी दी कि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने मार्च, 2015 में आईएफसीआई को "अनुसूचित जातियों के उद्यमियों के लिए ऋण वृद्धि गारंटी योजना" के कार्यान्वन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में पदनामित किया है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय के उद्यमियों को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं अर्थात् बैंकों की मार्फत ऋण वृद्धि गांरटी से वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जाति के बीच उद्यमीयता को बढ़ावा देना है।	

301

		इस योजना के तहत अनुसूचित जाति समुदाय के उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से 15 लाख से 15 करोड़ तक ऋण पर आईएफसीआई द्वारा गारंटी कवर दिया जाता है। उन्होने आगे जानकारी दी कि इस योजना की विस्तृत जानकारी IFCI के website से प्राप्त किया जा सकता है। **(एक्शन: सभी बैंक)**	
32	Digital Banking / Less Cash	एसएलबीसी बैठक के व्यवसायिक सत्र में Digital Banking / Less Cash पर चर्चा के दौरान NPCI के प्रतिनिधि श्री धीरेंद्र सिंह चौहान ने सभा को राज्य डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु NPCI के पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया। उन्होने जानकारी दी कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सभी Street Vendors को, जिन्हे बैंक से रु 10,000 का ऋण दिया गया है, उन्हे डिजिटल लेन-देन के लिए QR Code दिया जा रहा है। उन्होने व्यवसायियों को POS मशीन में लगने वाले चार्ज से बचने के लिए QR Code एवं UPI को अपनाने की सलाह दी। उन्होने राज्य के 19 Aspirational Districts एवं Digital District में भी डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने में अपना सहयोग देने की बात कही। आरबीआई के महाप्रबंधक श्री संजीव सिन्हा ने एसएलबीसी को सभी अग्रणी जिला प्रबन्धकों की एनपीसीआई के साथ एक Online Awareness Programme आयोजित करने के लिए सलाह दिया, जिससे वे इस जानकारी को जिलास्तर पर शाखाओं तक पहुंचा सकें। **(एक्शन: सभी बैंक, समस्त LDM, एसएलबीसी)**	
33	रामगढ़ RSETI भवन का निर्माण	विशेष सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार श्रीमती दीप्ती जयराज द्वारा सभा को संबोधित किया गया। श्रीमती दीप्ती जयराज ने कहा कि रामगढ़ RSETI भवन निर्माण हेतु आबंटित भूमि में आ रही बाधा को दूर करने के लिए वे स्वयं रामगढ़ जिला उपायुक्त से बात कर रही हैं एवं आशा है कि बहुत जल्दी	

76 वी. एसएलबीसी के बैठक के दौरान प्रमुख विंदुओ पर अपेक्षित कृत कार्यवाही रिपोर्ट

		ही इसका समाधान हो जाएगा, जिससे भवन निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा। **(एक्शन: बैंक ऑफ इंडिया)**	
34	डिजिटल ई-स्टांपिंग की प्रगति	विशेष सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार श्रीमती दीप्ती जयराज ने एसएलबीसी से डिजिटल ई-स्टांपिंग की प्रगति रिपोर्ट साझा करने को कहा और सभी बैंकों से अनुरोध किया कि सभी बैंक अपने लोन डॉकयुमेंट की डिजिटल ई-स्टांपिंग शुरू करें। उन्होंने एसएलबीसी को SLBC पोर्टल पर Standardized सिस्टम के तहत डाटा अपलोडिंग शुरू करने के लिए बधाई दी। साथ ही साथ उन्होने एसबीआई को सलाह दी कि राज्य के सबसे बड़े बैंक होने के नाते एसएलबीसी को दिये जाने वाले डाटा की सत्यता के प्रति उनकी सबसे ज्यादा ज़िम्मेदारी है एवं उन्हे इसपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। **(एक्शन: सभी बैंक)**	
35	Interest Subvention Scheme	सभा को विशेष सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग जानकारी दी गयी कि राज्य सरकार Government Business के लिए दो बैंकों का चयन कर रही है, जिसका आधार राज्य में उनका ग्रामीण शाखा नेटवर्क, बीमी नेटवर्क, शिक्षा ऋण, आवास ऋण एवं प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अतर्गत उपलब्धि रहेगी। अत: उन्होने सभी बैंकों को इस क्षेत्र में विशेष प्रयास करने हेतु सलाह दी। उन्होने बैंकों को Interest Subvention Scheme वाले सरकारी योजनाओं का विशेष प्रचार-प्रसार करने की सलाह दी। **(एक्शन: सभी बैंक)**	

सभी सदस्यों / हितधारको से आग्रह किया जाता है कि दिनांक 15 अक्टूबर 2021 तक संबन्धित विषय पर विस्तृत कृत कार्यवाही रिपोर्ट राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को अवश्य प्रेषित करें।

(गणेश टोप्पो)
उप महाप्रबंधक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति-झारखंड

2233
16.08.21

झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग,
नगरीय प्रशासन निदेशालय

दिनांक 29-07-2021 को निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय ,नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आहूत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की Housing Finance sub-committee की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

1. निदेशक , नगरीय प्रशासन निदेशालय
2. नगर आयुक्त , हजारीबाग नगर निगम
3. नगर आयुक्त , मेदिनीनगर नगर निगम
4. नगर आयुक्त , देवघर नगर निगम
5. अपर नगर आयुक्त , आदित्यपुर नगर निगम
6. अपर नगर आयुक्त , चास नगर निगम सहायक
7. सहायक निदेशक , नगरीय प्रशासन निदेशालय
7. विशेष पदाधिकारी , जमशेदपुर अ०क्षे०स०
8. कार्यपालक पदाधिकारी , दुमका , कोडरमा, सरायकेला, गढ़वा , मधुपुर बुंडू, मिहिजाम
9. सहायक महाप्रबंधक , SLBC
10. AGM, NHB
11. DM, Canara Bank
12. Axis Bank
13. State Bank of India
14 . Punjab National Bank
15. Bank of Baroda
16. Bank of India

बैठक के प्रारंभ में सर्वप्रथम श्री रुपेश कुमार , सहायक महाप्रबंधक , SBI –सह- संयोजक , SLBC Sub-committee on Housing Finance द्वारा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारी गण एवं बैंकर्स के राज्य प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया तथा बैठक के उदेश्यों पर विस्तार पूर्वक बताया गया। तत्पश्चात निदेशक महोदया द्वारा Housing Finance विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत किफायती आवास परियोजनाओं के लाभुकों को गृह ऋण (Home Loan) स्वीकृति की समीक्षा की गयी एवं निम्नलिखित निदेश दिए गए :-

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत किफायती आवास परियोजनाओं के लाभुकों को गृह ऋण (Home Loan)

- निदेशक महोदया द्वारा SLBC Sub-committee on Housing Finance की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक भागीदारी में किफायती आवास परियोजना (Affordable Housing in Partnership) के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होंने बताया कि राज्य के 16 नगर निकायों में तृतीय घटक के तहत 14,797 आवासों का निर्माण किया जा रहा है , जिसके तहत 3,154 पात्र लाभुकों को आवास आवंटित भी कर दिया गया है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक भागीदारी में किफायती आवास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रति आवास लागत का लगभग 40 % राशि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है (केंद्र सरकार रू० 1.50 लाख तथा राज्य सरकार रू० 1.00 लाख)। आवास की शेष राशि लगभग 60 % लाभुकों के द्वारा वहन किया जाना है , जो कि लगभग रू० 3.50 लाख से रू० 4.50 लाख के बीच है।

- यह परियोजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवास विहीन लाभुकों के लिए है , अतः परियोजना के सफलता हेतु विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। परियोजना के अधिकांश लाभुक आवास ऋण के माध्यम से आवास लागत की किश्तों का भुगतान करना चाहते हैं। ऋण की राशि भी प्रति लाभुक अधिकतम रू० 3.00 लाख से रू० 4.00 लाख के बीच होगी । निदेशक महोदया द्वारा बताया गया कि परियोजना का निर्माण कार्य लगभग 40 % से 50 % पूर्ण हो चूका है , किन्तु लाभुकों का अंशदान संग्रह नहीं होने के कारण परियोजना का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है।

- निदेशक महोदय द्वारा बताया गया कि नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा SLBC कि त्रैमासिक बैठकों में तथा SLBC Sub-committee on Housing Finance की बैठक में कई बार निदेश दिया गया है , किन्तु SLBC एवं बैंकर्स द्वारा लाभुकों को गृह ऋण स्वीकृति हेतु कोई भी सकारात्मक पहल नहीं किया गया है , यह अत्यंत खेदजनक है। SLBC को निदेश दिया गया कि अपने स्तर से सभी बैंकों को किफायती आवास परियोजनाओं के लाभुकों को Home Loan स्वीकृत करने हेतु निदेश दिया जाए।

2233
16.8.21

- PMAY-U के तृतीय घटक के लाभुकों को गृह ऋण प्रदान करने में सहूलियत हेतु नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा 7 बैंकों यथा Canara Bank, Allahabad Bank, Union Bank of India, Axis Bank, Central Bank of India, ICICI Bank एवं HDFC Ltd. के साथ MoU किया गया है , किन्तु Canara Bank को छोड़ कर अन्य बैंकों ने कोई पहल नहीं किया है। चूँकि निजी बैंक इस बैठक में शामिल नहीं हैं अतः इस संबंध में SLBC को निजी बैंकों ICICI Bank एवं HDFC Ltd. को गृह ऋण स्वीकृति हेतु सूचित करने का निदेश दिया गया।

- राज्य में एकमात्र Canara Bank द्वारा सकारात्मक पहल करते हुए राँची नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे " बन्होरा किफायती आवास परियोजना " के 70 लाभुकों को आवास ऋण प्रदान किया गया है , जिससे की लाभुकों में हर्ष है और अन्य लाभुक भी आवास लेने हेतु प्रात्साहित हुए हैं। निदेशक महोदया द्वारा Canara Bank कि प्रसंशा की गयी एवं अन्य बैंकों को भी निर्देश दिया गया कि लोन प्रक्रिया को और सरल करते हुए जरूरतमंद आर्थिक रूप से कमजोर लाभुकों को लोन मुहैया कराया जाए।

- पूर्व में निदेशालय के निदेशानुसार राज्य के नगर निकायों में निकाय क्षेत्र के बैंकर्स के साथ किफायती आवास परियोजनाओं के लाभुकों को होम लोन प्रदान करने हेतु बैठक आयोजित की गयी है। निकायों के द्वारा बताया गया है कि बैंकों के द्वारा होम लोन स्वीकृत करने की दिशा में सकारात्मक पहल नहीं किया जा रहा है , वरण कई तकनीकी कारणों का हवाला देकर गृह ऋण स्वीकृत करने में कोई रूचि नहीं लिया जा रहा है। जिससे कि लाभुकों में निराशा है और केंद सरकार की महत्वाकांक्षी योजना PMAY-U का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है।

- बैठक में उपस्थित सहायक निदेशक , नगरीय प्रशासन निदेशालय द्वारा बताया गया कि दिनांक 24-02-2021 को सचिव महोदय , नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में आहूत SLBC Sub-committee on Housing Finance की बैठक में सचिव महोदय द्वारा निदेश दिया गया था कि निकायों में निर्मित हो रहे किफायती आवास परियोजनाओं का भ्रमण बैंक के पदाधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए एवं आवश्यक जानकारी लेनी चाहिए। इस संबंध में बैंकों के आग्रह पर सभी परियोजनाओं की विस्तृत विवरणी नोडल अधिकारियों के मोबाइल नंबर के साथ निदेशालय पत्रांक 617 दिनांक 26-02-2021 द्वारा SLBC को सभी बैंकों को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित की गयी थी। पाँच माह बीत जाने के उपरांत भी Canara Bank को छोड़ कर अन्य बैंकों की प्रगति शून्य है। जिस पर निदेशक महोदय द्वारा सभी बैंकों से आगे बढ़कर लोन प्रक्रिया को और सरल करते हुए जरूरतमंद लाभुकों को गृह ऋण स्वीकृत करने का निदेश दिया गया।

- निदेशक महोदय द्वारा सभी निकायों के नगर आयुक्त / अपर नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी को निदेश दिया कि पत्र के माध्यम से बैंकों को लाभुकों के दस्तावेज एवं परियोजना से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएँ ताकि गृह ऋण की स्वीकृति समयबद्ध तरीके से किया जा सके ।

- विभिन्न निकायों के द्वारा बताया गया कि बैंकों के द्वारा अंचल कार्यालय से निर्गत आय प्रमाण पत्र नहीं स्वीकार किया जा रहा है , बैंकों के द्वारा Account Statement माँगा जा रहा है। कई बैंकों द्वारा Income Tax Return के प्रति की माँग की जा रही है।इस संबंध में अंचल कार्यालय से निर्गत आय प्रमाण पत्र को भी स्वीकार करने का निदेश दिया गया।

2233
16.8.21

किफायती आवास परियोजनाओं के तहत गृह ऋण (Home Loan) की अद्यतन स्थिति :

S.No.	ULB Name	Project Name	No. Of DUs	Per DU cost (In Rs. Lakhs)	Govt. Share (In Rs. Lakhs)	Beneficiary Share (In Rs. Lakhs)	House Allotment done	Home Loan Sanctioned by Banks
1	Adityapur	Kasidih AHP	780	6.41	2.5	3.91	545	0
2	Bundu	Tangartoli AHP	80	5.67	2.5	3.17	59	0
3	Chas	Kalapathar AHP	640	5.61	2.5	3.11	97	0
4	Deoghar	Mohanpur AHP	665	6.74	2.5	4.23	665	0
5	Dumka	Dudhani AHP	160	5.47	2.5	2.96	92	0
6	Garhwa	Sonpurwa AHP	400	6.46	2.5	3.96	160	0
7	Giridih	Karharbari AHP	190	6.24	2.5	3.74	129	0
8	Hazaribagh	Kolghatti AHP	288	6.14	2.5	3.64	254	0
9	Jamshedpur	Bagunhatu AHP	1,136	6.46	2.5	3.96	588	0
10	Jamshedpur	Birsanagar AHP	9,592	6.81	2.5	4.31	0	0
11	Jhumritelaiya	Telaiya AHP	80	5.62	2.5	3.12	34	0
12	Koderma	Bonakali AHP	90	5.62	2.5	3.12	32	0
13	Madhupur	Nawadih AHP	120	6.08	2.5	3.58	105	0
14	Medininagar	Aghori Ashram	240	6.41	2.5	3.91	176	0
15	Mihijam	Butberia AHP	96	6.14	2.5	3.64	55	0
16	Ranchi	Banhaura AHP	180	5.68	2.5	3.18	125	70 Canara Bank
17	Seraikela	Norodih AHP	60	6.41	2.5	3.91	38	0
			14,797				**3,154**	70

2233
16.8.21

2. लाइट हाउस परियोजना , राँची

- नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड के अधीन लाइट हाउस परियोजना , राँची का क्रियान्वयन राँची नगर निगम क्षेत्र के आनी , धुर्वा में किया जा रहा है। इस परियोजना में नयी एवं उभरती तकनीक (3D Volumetric Pre-cast) से आर्थिक रूप से कमजोर आवासविहीन लाभुकों के लिए 1008 फ्लैट का निर्माण किया जा रहा है। निदेशक महोदय द्वारा बताया गया कि यह परियोजना झारखण्ड के लिए अति प्रतिष्ठित परियोजना है। भारत के मात्र 6 शहरों यथा राँची , लखनऊ, राजकोट , इंदौर , चेन्नई एवं अगरतल्ला में LHP PROJECT का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- लाइट हाउस परियोजना , राँची के अंतर्गत प्रति आवास की लागत रू०13.29 लाख है , जिसमे केंद्र एवं राज्य सरकार का अंशदान रू० 6.50 लाख प्रति आवास है तथा शेष राशि रू० 6.79 लाख लाभुक को स्वयं वहन करना है। इस परियोजना के सफलता हेतु अधिक से अधिक लाभुकों को गृह ऋण प्रदान करने हेतु सभी बैंकों को निदेश दिया गया।

3. PMAY Urban अंतर्गत द्वितीय घटक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)

- PMAY Urban के दूसरे घटक Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) अंतर्गत EWS (Economically Weaker Section)/LIG (Low Income Group)/MIG(I) (Middle Income Group) एवं MIG(II) के लाभुकों को आवास निर्माण, क्रय अथवा आवास के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाता है । इस योजना के माध्यम से गृह ऋण के ब्याज दर में योजना के प्रावधानों के अनुसार छुट दी जाती है। इस घटक के प्रचार प्रसार एवं लाभुकों को ऋण प्रदान करने हेतु SLBC के एजेंडा में भी इस विषय को शामिल कराया गया है।
- CLSS की अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार पुरे राज्य 12,965 परिवारों को कुल 1,946 करोड़ का गृह ऋण स्वीकृत किया गया है। जिसके तहत हाउसिंग फाइनेंस कम्पनी LIC Housing Finance Ltd. द्वारा सबसे अधिक 4554 लोन स्वीकृत किया गया है। CLSS लोन स्वीकृति में State Bank of India, Canara Bank एवं ICICI Bank Ltd.का प्रदर्शन संतोषजनक है , जबकि शेष बैंकों द्वारा इस घटक के तहत लोन स्वीकृति में विशेष रुचि नहीं ली जा रही है। इस सन्दर्भ में निदेशक महोदय द्वारा SLBC को निदेश दिया गया कि सभी बैंकों के साथ मासिक समीक्षा करते हुए निदेशालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

Consolidated PMAY Vertical 2- CLSS Report

Sl.No.	Name of PLIs (Banks & HFCs)	EWS Beneficiaries	LIG Beneficiaries	MIG-I Beneficiaries	MIG-II Beneficiaries	Total beneficiaries	Total Loan Amount (in Crore)
1	LIC Housing Finance Ltd.	170	1835	2250	299	4554	503.91
2	SBI LHO-Patna	52	1464	2209	447	4172	737.11
3	State Bank of India	13	346	391	81	831	144.49
4	Canara Bank	12	217	345	51	625	70.89
5	ICICI Bank Ltd.	22	154	244	48	468	104.9
6	IDBI Bank Ltd.	3	105	213	16	337	55.74

2233
16.8.21

7	United Bank of India	13	86	162	24	285	49.08
8	HDFC	6	68	91	16	181	29.64
9	Allahabad Bank	8	31	115	20	174	32.78
10	Oriental Bank of Commerce	9	55	67	10	141	17.6
11	Tata Capital Housing Finance Ltd.	17	54	49	4	124	26.01
12	Bank of India	5	24	51	14	94	19.64
13	Punjab National Bank	4	21	51	15	91	15.74
14	Dewan Housing Finance Corporation Ltd.	9	31	40	9	89	15.43
15	PNB Housing Finance Ltd.	8	48	27	5	88	18.96
16	Shubham Housing Development Finance Company Pvt. Ltd.	40	35	8	1	84	3.63
17	Bank of Baroda	9	13	51	6	79	12.12
18	Central Bank of India	4	18	40	3	65	11.15
19	Indian Bank	4	38	17	2	61	6.22
20	Andhra Bank	0	18	32	10	60	9.8
21	Axis Bank Ltd.	0	14	26	6	46	10.23
22	Bank of Baroda	0	1	43	0	44	10.42
23	Vijaya Bank	11	17	10	2	40	5.63
24	Aadhar Housing Finance Ltd.	9	11	7	0	27	1.82
25	Indian Overseas Bank	1	6	18	2	27	4.96
26	Syndicate Bank	1	9	13	2	25	4.04
27	Union Bank of India	0	5	15	2	22	5.54
28	Corporation Bank	1	5	13	2	21	4.37
29	Bandhan Bank Ltd	9	9	0	0	18	0.67
30	Jharkhand Rajya Gramin Bank	1	12	0	1	14	2.05
31	Aditya Birla Housing Finance Ltd.	0	10	2	0	12	1.99
32	Punjab & Sind Bank	0	2	8	0	10	1.52
33	Bank of Maharashtra	0	3	4	2	9	0.91

2233
16.8.21

34	UCO Bank	0	0	9	0	9	1.75
35	Ujjivan Small Finance Bank	2	4	0	0	6	0.58
36	South Indian Bank Limited	0	5	0	1	6	1.13
37	KarurVysya Bank Ltd.	0	3	0	0	3	0.25
38	SBI LHO-Kolkata	0	2	1	0	3	0.6
39	SBI LHO-Bhopal	0	0	1	2	3	0.34
40	Dena Bank	0	0	2	0	2	0.17
41	Karnataka Bank Ltd.	0	0	2	0	2	0.41
42	Utkarsh Small Finance Bank Ltd	0	2	0	0	2	0.4
43	J&K Bank Ltd.	1	1	0	0	2	0.09
44	SBI LHO-Bhopal	0	0	1	1	2	0.32
45	ICICI Home Finance Company Ltd.	0	1	0	0	1	0.16
46	Repco Home Finance Ltd.	0	1	0	0	1	0.19
47	Sahara Housing FinaCorporation Ltd.	0	1	0	0	1	0.04
48	Bajaj Housing Finance Ltd	0	0	0	1	1	0.38
49	The Federal Bank Ltd	0	0	1	0	1	0.21
50	SBI LHO-Chandigarh	0	0	1	0	1	0.11
51	SBI LHO-Delhi	0	0	0	1	1	0.4
	Grand Total	**444**	**4785**	**6630**	**1106**	**12965**	**1946.52**

अंत में बैठक के समापन पर श्री रुपेश कुमार , सहायक महाप्रबंधक , SBI –सह- संयोजक , SLBC Sub-committee on Housing Finance ने सभी पदाधिकारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी एवं जनकल्याणकारी योजना है , जिसके तहत शहरी आवासविहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। SLBC द्वारा इस संबंध में सभी बैंकों के साथ नियमित समीक्षा की जाएगी एवं उन्हें अधिक से अधिक होम लोन स्वीकृति करने हेतु निदेश दिया जाएगा।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

निदेशक,
नगरीय प्रशासन निदेशालय
नगर विकास एवं आवास विभाग,

ज्ञापांक : 2233 दिनांक : 16-08-2021

प्रतिलिपि: महाप्रबंधक , राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति/ सहायक महाप्रबंधक , SBI –सह- संयोजक , SLBC Sub-committee on Housing Finance को आवश्यक कार्यार्थ एवं सभी बैंकों के राज्य प्रमुखों को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

निदेशक
नगरीय प्रशासन निदेशालय ,
नगर विकास एवं आवास विभाग,

ज्ञापांक : 2233 दिनांक : 16-08-2021

प्रतिलिपि: सम्बंधित नगर निकायों के नगर आयुक्त /अपर नगर आयुक्त /कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित।

निदेशक
नगरीय प्रशासन निदेशालय ,
नगर विकास एवं आवास विभाग,

ज्ञापांक : 2233 दिनांक : 16-08-2021

प्रतिलिपि: प्रधान सचिव , वित्त विभाग / सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
नगरीय प्रशासन निदेशालय ,
नगर विकास एवं आवास विभाग,

MINUTES OF SLBC SUB COMMITTEE MEETING ON SECURITY HELD ON 31.07.2021 THROUGH WEBINAR

The SLBC Sub-committee meeting on Security aspect of Banks for the June – September quarter was held through WEBINAR on 31.07.2021. The meeting was chaired by Shri Prashant Singh, ADG(C.I.D.), Ranchi, attended by representatives of SLBC and other commercial Banks . Shri Rupesh Kumar, AGM, State Bank of India welcomed the participants

Agenda No -1 – Confirmation of the last meeting held on 25.02.2020:
Action Taken Report of previous meeting was discussed and thereafter all participants confirmed the proceedings of the previous meeting.

Agenda No- 2.- Discussion on recent cases of dacoity/ Burglary by participating Banks :
No such incident happened in recent past, there was no discussion at length on this issue.

Agenda No- 3 Discussion on recent cases of fire at Branches / ATMs:
As no such mishaps have taken place in recent past, there was no discussion at length on this issue.

Agenda No- 4- Provision of round the clock patrolling around Bank Premises during holidays / night hours.
Shri Prashant Singh has informed that communication has been sent to all S.S.P/S.P. to enhance security cares of bank branches through patrolling in their jurisdiction.

Agenda No. 5- Discussion on Karnataka Model on cyber crime.
A healthy discussion has been done among the banks and requested to furnish Nodal officer Name / contacts / address / and generic email ids for sharing. Shri Prashant Singh (ADG, CID) has assure that they are ready to share their Nodal officer Name / contacts / address to all.

Agenda No. 5- . Any other issue with the permission of the chair
There was no discussion at length on this issue.
The meeting concluded with vote of thanks by Shri Rupesh Kumar, AGM, SBI.

(Prashant Singh)
Add. DG, CID,
Jharkhand, Ranchi.

Letter No. 257 /O.C.(EO)

CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT, JHARKHAND, RANCHI.

Ranchi, Dated :- 6/8/2024

Copy :-

1. Director General of Police, Jharkhand, Ranchi for kind information please.
2. All Range Deputy Inspectors General of Police (including Rail), Jharkhand for information and necessary action.
3. SSP, Ranchi, Jamshedpur, Dhanbad / All Superintendents of Police (including Rail), Jharkhand for information and necessary action.
4. AGM, RBI, Ranchi for information and necessary action.
5. AGM, (SLBC) SBI, Ranchi for information and necessary action.
6. Nodal Officers of SLBC for information and necessary action.

6/8

Add. DG, CID,
Jharkhand, Ranchi.

Govt. of Jharkhand
Rural Development Department
Jharkhand State Livelihood Promotion Society

Letter No- JSLPS/711 Date- 19/08/2021

Meeting minutes of 26th SLBC RSETI Cub-Committee meeting held online on 5th August, 2021

26th SLBC-RSETI sub-committee meeting was held online on 05th of August, 2021 under the chairmanship of Mr. Manish Ranjan, IAS, Secretary, RDD, GoJ. Ms. Nancy Sahay, CEO, JSLPS, RDD, GoJ welcomed all the participants. The meeting was attended by COO, JSLPS, DGM SLBC, AGM RBI, AGM NABARD, senior officials of State Bank of India, Bank of India, Indian Bank, Punjab National Bank, Canara Bank, State Director for RSETI and all RSETI Directors along with State Nodal officer, RSETI.

Secretary, RDD addressing the house, emphasized the need to ensure credit linkage to all the willing candidates and settlement of the trained candidates should be the key objective of RSETIs/RUDSETIs. He stressed the need to ensure safety of all during the training, to start the training by following appropriate COVID-19 behavior and follow the guidelines issued by MoRD and GoJ from time to time.

Agenda-wise details of the meetings are:

Action Taken Report (ATR) of last sub-committee meeting

Action taken report was received from only SBI and BOI. Reports were pending from Indian Bank, Canara Bank and PNB. It was requested by CEO to submit action taken reports as per the discussion held in the sub-committee meeting before the commencement of next sub-committee meetings regularly.

All the banks were requested to share the details (Name, Designation, Email id and Contact Number) of the officers looking after RSETI affairs to the department by 15th of August, 2021.

Action to be taken: All Banks

Training and Settlement:

Due to COVID-19 pandemic, the training institutes were closed since April 2021. However, it was informed to the house that the notification to start the training center has been given by state government. Also, a letter in this regard has also been issued by CEO, JSLPS to all RSETIs/RUDSETI. However, it was directed that all COVID-19 guidelines issued from State government and Central government needs to be strictly followed during the training.

It was also directed to all RSETI/RUDSETIs that as per direction of MGNREGA Commissioner, the training under Project UNNATI needs to be started on priority by 15th of August, 2021. A letter from MGNREGA Commissioner in this regard has been sent to all DCs/DDCs to ensure the same.

It was also discussed to ensure post training follow up of all candidates to improve the ensure settlement rate.

Action to be taken: All Banks

Manish Ranjan

Scanned with CamScanner

Credit Linkage to trained candidates:

It was discussed that credit linkage of trained candidates is still a cause of concern. Most of the applications submitted is being rejected by banks. CEO, JSLPS emphasized the need to improve credit linkage so that no candidates is left unsettled due to lack of funds. It was highlighted in the meeting that during the current FY, only 223 loan application have been sanctioned till 30.07.2021 whereas 363 applications have been rejected. There are 3622 application still pending across districts. SLBC is requested to closely monitor the progress and submit a report regarding high reasons for rejection and pendency of applications in the next sub-committee meeting.

Action to be taken: SLBC, All Banks

Completion of RSETI Building:

It was informed to the house that building construction of RSETI Dumka and RUDSETI has been completed and training started in the new building. After these two RSETIs, total RSETI building completed is 16.

Bank wise RSETI Buildings under construction are:

Garhwa, Sahebgang, Jamtara, Latehar, Ranchi, Palamu, Pakur (SBI)
Godda (Indian Bank), Lohardaga (BOI)

HR Status as per SOP:

As per the reports submitted by Banks, it has been ensured that the HR status as per SOP in under progress and that the HR will be completed by 31st of August, 2021. It was requested to all the banks to finalize HR as per the SOP in all RSETIs by 31st of August, 2021.

Action to be taken: SLBC, All Banks

Other Agenda:

It was informed to the house that pending claims for FY 2019-20 to the tune of Rs. 77 lakhs have been processed from JSLPS and other pending claims will be cleared in due course of time.

Yours Sincerely,

Manish Ranjan

Secretary
Rural Development Dept.,
Govt. of Jharkhand

Scanned with CamScanner

Govt. of Jharkhand
Rural Development Department
Jharkhand State Livelihood Promotion Society

Letter No..JSLPS/710 Date:..19/08/2021

Minutes of the 34th SLBC Sub-Committee meeting (SHGs-Bank linkage and NRLM Coordination)

The 34th meeting of SLBC Sub-Committee (SHGs-Bank linkage and NRLM Coordination) was organized online on 5th August 2021. The Secretary, Rural Development Department, Govt. of Jharkhand chaired the meeting. The Chief Executive Officer, JSLPS, Rural Development Department, Govt. of Jharkhand welcomed participants and moderated the meeting.

Agenda wise discussions and decisions are as follows –

Agenda 2	Review of SHGs-Credit linkage progress (Bank wise) in the FY 2021-22 and planning of Q-2.
Discussion and decision	* According to SHG-Bank linkage Portal of DAY-NRLM, total **36,697** SHGs have been disbursed loan **(29%)**, disbursed amount is **Rs. 200.74 Crore (14%)** and outstanding amount is **Rs. 1264.15 Crore** (82%) against target in the FY 2021-2022. Bank wise achievement may be seen in ***Annexure I.*** * Total **1,53,214** SHGs have been credit linked out of **2,42,054** saving bank accounts opened in different banks. Bank wise details can be seen in ***Annexure II.*** * Total **12,843** documents are pending and **3,264** documents are being slowly received in different bank branches for credit linkage (hence in the hands JSLPS field staffs) as on 15th July 2021. Bank wise details can be seen in ***Annexure III.*** The JSLPS is targeting to submit **10,000** additional documents for credit linkage in August 2021. * The Secretary, Rural Development Department, Govt. of Jharkhand, instructed all Banks to increase loan disbursement to SHGs and achieve 60 percent of the annual target by 10th September with the support from JSLPS team. * The CEO, JSLPS, Rural Development Department, requested all Banks to dispose all pending documents of SHGs Credit linkage submitted in Bank Branches in a drive mode in the month of August through small camps following COVID 19 protocols. She asked Banks to do credit linkage of 88,840 SHGs having saving bank accounts opened in different Banks but not yet credit linked. * Controlling Heads / Representatives of all Banks ensured to increase loan disbursement to SHGs, disposal of pending documents and speed up credit linkage of SHGs in the month of August. * Representative of RBI suggested to organize Financial Literacy Camps to smoothen local level issues.
Agenda 3	Engaging SHG members as BC Agents and ensuring dual authentication mapping of SHG loan account / saving bank account with members saving bank accounts for transaction at BC point.
Discussion and decision	* As on date Jharkhand Rajya Gramin Bank engaged 486 SHG members as BC Agents, Bank of India - 216, State Bank of Indias-140, Punjab National Bank-12, Bank of Baroda-35, Canara Bank-23, IDFC – 97, Union Bank of India- 60, Indian Bank-1, Central Bank of India-6, Fino Payment Bank- 4 and DigiPay (CSC) - 3540 (total= 4620). All Banks are requested to engage SHG members as BC Agents as many as possible. * The CEO, JSLPS, requested all Banks to appoint SHG members as Bank BC Agents in all Gram Panchayats as soon as possible. Total 3540 trained DigiPay Agents can be appointed as Bank BC in priority basis. *All Banks were requested to push dual authentication mapping of SHG loan / saving bank account with members saving bank accounts for transaction at BC point.

Scanned with CamScanner

Agenda 4	Accelerate enrolment of SHG members under PMSBY, PMJJBY and APY and sharing of enrolment data Bank branch wise to JSLPS. Accelerate claim settlement under PMJJBY and PMSBY.
Discussion and decision	* It was informed by JSLPS that 33 lakh rural women have been organized under 2.63 lakh SHGs in the State under DAY-NRLM. As per the instruction received from Ministry of Rural Development, Government of India, all SHG members and their spouses should be covered under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY), at least 70 percent of them under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojna (PMJJBY) and 10 to 15 percent under Atal Pension Yojna (APY) by September 2021. The JSLPS has already initiated mobilizing all SHGs members to enroll under these schemes. * The Secretary, Rural Development Department, Govt. of Jharkhand, instructed all Banks to initiate campaign to enroll all SHG members and their spouses under these insurance and pension schemes and achieve at least 60 percent of the target by 10th September 2021. He added that one-month special drive on insurance and pension for SHG members and their spouses will be initiated by JSLPS within two to three days. * At present, total 80 documents are under process in different Bank Branches for claim settlement under PMSBY and PMJJBY. In State Bank of India 13 documents are under process, Jharkhand Rajya Gramin Bank-18, Bank of India-32, Punjab National Bank- 1, Canara Bank- 8, Indian Overseas Bank-1, Indian Bank- 4, UCO Bank-1 and Bank of Baroda-2). * All Banks were requested to follow up the pending documents at Branch level and settle the claim as soon as possible in this COVID 19 pandemic period to help such families immediately. * Representative of Bank of India shared that Saturday is fixed for insurance and pension enrollment in all Bank Branches of Bank of India across the State. All Banks were requested the fix a day per week for enrollment and claim settlement for insurance and pension in all Bank Branches and share it to JSLPS and other stakeholders.
Agenda 5	Any other issue by permission of the chair.
Discussion and decision	* The Secretary, Rural Development Department, Govt. of Jharkhand, instructed representatives of all Banks to come prepared with the progress report and other required information in the meeting.

The meeting ended with vote of thanks to all participants by the Chief Executive Officer, JSLPS, Rural Development Department, Govt. of Jharkhand.

Enclosed: Annexure

Yours Sincerely,

Alok Raja

Secretary
Rural Development Dept.,
Govt. of Jharkhand

Scanned with CamScanner

Minutes of SLBC Sub-Committee Meetings on C.D. Ratio and ACP/NPA/MSME/ Steering Committee / Export Finance on 09.08.2021

SLBC Sub-Committee Meetings on C.D. Ratio and ACP/NPA/MSME/Steering Committee / Export Finance were convened through VC on 09.08.2021 through virtual mode (Google meet).

The meeting was chaired by Mr.Ganesh Toppo, Deputy General Manager, SLBC-Jharkhand. The meeting was also attended by AGM RBI, DGM NABARD, representative from Department of Planning Cum Finance- GoJ, and Senior Officers from Member Banks of the Committee as per list enclosed.

On inaugural remark Mr. Ganesh Toppo welcomed all the participants in the meeting and set out the context of the meeting and briefed the house on various Agenda items. Thereafter as per the Agenda items following points were discussed in detail and action points emerged as under:

1) Bank Wise / District wise review of CD ratio:

The house expressed concern over sharp decrease in CD ratio in the State. The CD ratio has decreased to 37.04% as on 30.06.2021 from 42.43% as on 31.03.2021. It is far below the benchmark level of 60%. Specifically, the performance of 18 Banks and 21 Districts having less than 40% CD ratio as on 30.06.2021 were reviewed /discussed during the meeting. It was discussed that sharp reduction in CD Ratio is may be due to data collection as per standardized Automated Data flow system of LBS guidelines. It was decided to instruct the Banks and LDMs for make focussed efforts in this matter, make Monitorable Action Plan, review it at regular intervals at district level and improve the CD ratio in a proactive manner. DGM, NABARD suggested to conduct some study on CD ratio though Independent agency so that based on outcomes of study, proper strategies can be formulated to enhance CD Ratio. AGM, RBI advised NABARD to take a lead in the matter concerned.

BANK WISE CD RATIO BELOW 40% - AT THE END OF JUNE 2021 (18 BANKS):

BANK OF MAHARASHTRA (39.26%); JHARKHAND RAJYA GRAMIN BANK (38.52%); BANK OF BARODA (37.21%); FEDERAL BANK (35.49%); INDIAN OVERSEAS BANK (32.02%); IDBI BANK (31.09%); PUNJAB NATIONAL BANK (30.19%); JHARKHAND STATE COOPERATIVE BANK LTD (30.03%); UNION BANK OF INDIA (26.94%); STATE BANK OF INDIA (26.70%); INDIAN BANK (26.34%); PUNJAB AND SINDH BANK (24.70%); BANK OF INDIA (23.04%); CENTRAL BANK OF INDIA (22.09%); UCO BANK (18.08%); CANARA BANK (11.49%); SOUTH INDIAN BANK (11.44%); DHANBAD CENTRAL COOPERATIVE BANK (9.38%).

District Wise CD Ratio Below 40% - AT THE END OF JUNE 2021 (21 Districts):

LOHARDAGA (39.30%); E.SINGHBHUM (38.75%); HAZARIBAGH (37.08%); GARHWA (35.90%); RANCHI (34.13%); DHANBAD (33.25%); KODERMA (32.76%); GIRIDIH (32.55%); KHUNTI (32.50%); RAMGARH (32.37%); SAHIBGANJ (30.80%); LATEHAR (30.64%); DEOGHAR (30.37%); GODDA (29.95%); DUMKA (29.45%); BOKARO (28.15%); CHATRA (25.73%); GUMLA (24.33%); JAMTARA (24.12%); SIMDEGA (21.02%); W.SINGHBHUM (7.95%).

(Action- NABARD, Banks & LDMs)

2) Bank wise / District wise review of ACP achievement during 1St quarter of FY 2021-22 :

The performance of the banks under ACP for FY 2021-22 was reviewed and discussed. Overall ACP achievement in 1st quarter of FY 2021-22 is 17.39% higher than the performance of last Year's 1st quarter (June 2020) i.e. 18.75%. Overall ACP achievement is at 36.14% (Rs.16,043.57 Crores) against the target of 44,388.44 crores. There is improvement in performance of banks under the sector of Agriculture, MSME, TPS, and NPS, however there is decline in the achievement under Other Priority Sector as compared to Last year's 1st quarter. ACP achievement under other Priority sector and Agriculture sector requires to be improved further.

(Action- NABARD, LDMs & All Banks)

Achievement in Agriculture Sector is 12.57 % which is not satisfactory. Although there is improvement of 5.86% in Agriculture sector as compared to June quarter of last Financial Year but it needs huge improvement. Banks were asked to formulate suitable action plan for improvement in Agriculture Sector. DGM, NABARD suggested that focus should be given to KCC Saturation Drive including KCC (Crop production and allied activities) to PM KISAN beneficiaries and increase in credit flow to agriculture allied activities through Agriculture Infrastructure Fund, Animal Husbandry Infrastructure Fund, FPO financing etc.

(Action- NABARD, LDMs & All Banks)

ACP achievement in MSME sector is 40.59%. The current achievement in MSME sector is well above the last year achievement i.e., 25.90%. Banks were advised to continue this pace by active participation in PSBLOANsin59 minutes, MUDRA, PMEGP & other MSMEs schemes. Special focus to be given under COVID-19 various credit related Atma Nirbhar Bharat package, announced by GOI.

(Action- LDMs & All Banks)

3) Position of MSME Sector:- Total MSME (Sector wise) position in Jharkhand state was discussed in the meeting. SLBC informed that performance of banks under MSME sector of ACP is satisfactory but total MSME portfolio has been reduced from 26,853 Crores in June 2020 to 22,125 Crores in June 2021. All banks were advised to increase MSME portfolio of

banks and also try to achieve target under MSME sector of ACP in present Financial Year.

(Action: All Banks)

4) Review of NPA:- NPA Position was discussed in the Sub Committee meeting.

a) There is increase in Gross NPA as compared to last year. Gross NPA has been reached to 9.82% as on 30.06.2021. Banks should try all possible ways for better recovery. AGM, RBI requested banks to share the list of branches having NPA of more than 40% with SLBC for further submission to RBI.

(Action: All Banks)

b) The house was informed regarding taking suitable action plan for early resolution of pending SARFAESI, DRT & Certificate Case etc. in the Banks. It is also inform that there are 245 SARFAESI cases pending at District level. It was also requested to all the Banks to provide updated information regarding all Pending cases to SLBC for further submission to Planning cum Finance, GoJ.

(Action: All Banks)

c) The District co-ordinators of the Banks were advised to make proper liaison with DC & LDMs for early resolution of pending cases under SARFAESI, DRT, Certificate case etc. SLBC informed the house that Certificate officers have already been appointed in 10 districts which will help banks in recovery in certificate cases.

(Action: All Banks)

d) NPA position under various Govt. Sponsored Schemes were also discussed. As on 30.06.2021, there is 33.91% NPA under PMEGP loans, 23.47% under StandUp India, 9.67% under SHG and 9.29 % under PMMY. Banks should explore the recovery in these NPA accounts.

(Action: All Banks)

5) Export Finance: As per the data received from banks it was noticed that total Export Finance of all banks in the state has reduced from March, 2021 to June, 2021 i.e., from 2784.27 Lacs to 63.50 Lacs. However after discussion with banks, SBI and Union Bank reported that they have portfolio of export finance, but due to technical snag in the system the figure could not be reflected while submitting data to SLBC. SBI reported its export finance outstanding as 1690.01 lacs and Union Bank of India as 50.01 lacs. Therefore total export Finance portfolio of banks in Jharkhand is 1803.52 lacs as on 30.06.2021.

(Action: All Concerned Banks)

The meeting ended with a vote of thanks.

Date :19.08.2021

(Ganesh Toppo)
Deputy General Manager
SLBC-Jharkhand